PK टाइम्स

लोक टुडे

विश्वसनीय खबरों का सर्वश्रेष्ठ अखबार

pktimesnews.com
loktodaynews.com
PK Times News
thepktimesofficial
pk_timesofficial

वर्ष: 12 | अंक: 318 | मूल्य: 1.00 रुपए | पृष्ठ: 4 | बुधवार 03 जून 2026 | RNI No. RAJHIN/2013/50649

सावधान!

गाड़ियों में कराया अवैध बदलाव और लगाया गुप्त केबिन तो सीधे होगी जब्ती

अवैध मॉडिफिकेशन कर तस्करी करने वाले असामाजिक तत्वों पर 'जीरो टॉलरेंस'

- परिवहन और पुलिस विभाग चलाएंगे संयुक्त अभियान
- राजस्थान सरकार के सख्त आदेश जारी

लोक टुडे। जयपुर

वाहनों में अवैध मोडिफिकेशन कर मादक पदार्थों का परिवहन एवं अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त असामाजिक तत्वों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। इस पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर विशेष अभियान शुरू करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग तथा पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदेशव्यापी जांच और जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस सख्त कदम के पीछे सरकार की मंशा अपराधियों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करना है। हाल ही में राज्य सुरक्षा एजेंसियों और परिवहन विभाग के संज्ञान में आया है कि तस्करों और असामाजिक तत्वों द्वारा गाड़ियों (विशेषकर एसयूवी और ट्रकों) के चेसिस, बॉडी और आंतरिक संरचना में अवैध बदलाव किए जा रहे हैं। इन गुप्त केबिनों और मॉडिफिकेशन्स का उपयोग मुख्य रूप से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों के परिवहन और अन्य अपराधों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है। प्रदेशभर में ऐसे वाहन स्वामियों के खिलाफ चालान, जब्ती एवं अन्य कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए सभी क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

चालान के साथ ड्राइविंग लाइसेंस होगा निरस्त

विभाग ने स्पष्ट किया है कि वाहन की संरचना, बॉडी, चेसिस में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिससे वाहन के पंजीकरण प्रमाण-पत्र में दर्ज मूल विवरण प्रभावित हो। वाहन का प्रकार, सीटिंग क्षमता, रंग एवं आयाम अथवा निर्माता द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों से भिन्न कोई भी परिवर्तन अवैध माना जाएगा। किसी वाहन पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना लाल या नीली बत्ती, फ्लैशर, स्ट्रोब लाइट, बीकन लाइट, हूटर, प्रेशर हॉर्न, एयर हॉर्न अथवा निर्धारित मानकों के विपरीत ध्वनि उपकरण पाए जाने पर उन्हें मौके पर ही हटाया जाएगा। ऐसे मामलों में चालान के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेंस अयोग्य घोषित करने अथवा निरस्त करने की कार्रवाई भी होगी।

आरटीओ चलाएगा विशेष अभियान

परिवहन विभाग के संज्ञान में आया है कि असामाजिक तत्वों द्वारा वाहनों में अवैध मोडिफिकेशन कर मादक पदार्थों का अवैध परिवहन सहित अन्य गैर कानूनी गतिविधियां करने की संभावनाएं रहती हैं। वाहनों पर नियम विरूद्ध प्रतीक आदि लगाकर आमजन को भयभीत किए जाने की भी सूचनाएं मिलती हैं। ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के तहत मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के प्रावधानों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के लिए यह विशेष अभियान चलाया जाएगा।

हाई सिक्योरिटी प्लेट पर विशेष फोकस -

परिवहन विभाग ने सभी वाहन स्वामियों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के निर्देश दिए हैं। फर्जी नम्बर प्लेट, अपठनीय नम्बर प्लेट, नम्बर प्लेट को स्टिकर या अन्य सामग्री से ढंकना अथवा नम्बर प्लेट पर अनाधिकृत शब्द, चिन्ह या मोनोग्राम प्रदर्शित करना गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में वाहन का चालान, जब्ती तथा आवश्यकता पड़ने पर पंजीकरण निलंबन की कार्रवाई होगी।

वाहन मालिकों को 3 दिन की मोहलत

परिवहन विभाग ने राज्य के सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि यदि उनके वाहनों में अवैध मॉडिफिकेशन, नियम विरूद्ध नम्बर प्लेट अथवा अन्य उल्लंघन हो रहा है तो वे परिपत्र जारी होने की तिथि से तीन दिवस के भीतर उन्हें स्वयं ठीक कर लें। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद प्रदेशभर में विशेष जांच एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। उल्लंघन पाए जाने पर चालान, वाहन जब्ती तथा अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि वाहनों में मॉडिफिकेशन कर गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाना एवं सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे असामाजिक तत्वों एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अवैध मॉडिफिकेशन पर सख्त कार्रवाई -

परिवहन विभाग के अनुसार राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन संचालित होने की सूचनाएं सामने आती हैं, जिनमें नियमों के विपरीत अवैध मोडिफिकेशन, प्रेशर हॉर्न, एयर हॉर्न, अनाधिकृत लाल एवं नीली बत्तियां, फ्लैशर, हूटर, काली फिल्म, नियम विरूद्ध नम्बर प्लेट, अनाधिकृत शब्द, चिन्ह एवं लेखन प्रदर्शित किए जा रहे हैं। ऐसे वाहनों का उपयोग गैर कानूनी गतिविधियों एवं अपराधों में भी किए जाने की संभावना रहती है। मोडिफिकेशन के कारण वाहनों की पहचान नहीं होने से अपराधियों को पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। साथ ही, सड़क सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। ऐसी अवांछित गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम के लिए राज्यभर में व्यापक जन-जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वाहन स्वामी स्वेच्छा से नियमों का पालन सुनिश्चित कर सकें।

चार दशक का रसूख दांव पर: सचिन पायलट का बढ़ता प्रभाव

क्या थमेगी 'जादूगर' की छड़ी की रफ्तार?

पिछले चुनावों के मुकाबले बेहद पेचीदा होने वाला है 2028 का रण

भारती जैन। जयपुर

साल 2028 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में 'जादूगर' (अशोक गहलोत) की जादुई छड़ी का जादू चलना काफी हद तक उनके राजनीतिक फैसलों और पार्टी के भीतर बदल रहे समीकरणों पर निर्भर करेगा। राजस्थान की राजनीति में तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत को अपनी सियासी चालों के कारण 'जादूगर' कहा जाता है। लेकिन 2028 का रण उनके लिए पिछले चुनावों के मुकाबले कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। राजस्थान की राजनीति में जब भी बड़े नेताओं की बात होती है, तो अशोक गहलोत का नाम सबसे ऊपर आता है। करीब चार दशक से ज्यादा लंबे राजनीतिक करिअर में गहलोत ने न सिर्फ कांग्रेस को कई बार सत्ता तक पहुंचाया, बल्कि खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो संकट के समय भी पार्टी को संभालना जानते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या 2028 का विधानसभा चुनाव अशोक गहलोत के राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन चुनाव साबित होने वाला है? क्या राजस्थान कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की आहट सुनाई देने लगी है? और क्या सचिन पायलट का बढ़ता प्रभाव गहलोत की राजनीतिक विरासत के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है?

दो धड़ों में बंटी कांग्रेस

दरअसल, पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान कांग्रेस के भीतर दो स्पष्ट धड़े दिखाई दिए हैं। एक तरफ अशोक गहलोत का अनुभवी और संगठन पर मजबूत पकड़ वाला खेमा है, तो दूसरी तरफ सचिन पायलट का युवा और आक्रामक नेतृत्व। 2020 की राजनीतिक उठापटक के बाद दोनों नेताओं के बीच मतभेद खुलकर सामने आए थे। हालांकि पार्टी हाईकमान ने समय-समय पर स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन अंदरूनी खींचतान पूरी तरह खत्म नहीं हुई।

बदलते आंतरिक समीकरण — क्या राजस्थान कांग्रेस के भीतर शुरू हो चुकी है बड़े बदलाव की सुगबुगाहट?

सबसे बड़ी चुनौती पायलट

यहीं से गहलोत के सामने एक और चुनौती खड़ी होती है। अगर भविष्य में कांग्रेस सत्ता में वापसी की रणनीति बनाती है, तो क्या पार्टी पुराने नेतृत्व के साथ आगे बढ़ेगी या फिर युवा चेहरे को मौका देगी? यह सवाल आने वाले समय में और ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब जादूगर के आगे चुनौतियों की भी कमी नहीं है। उन्ही चुनौतियों में से एक हैं सचिन पायलट, जो लगातार खुद को एक जननेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। युवाओं, किसानों और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर उनकी सक्रियता उन्हें कांग्रेस के भीतर एक मजबूत दावेदार बनाती है। पायलट समर्थकों का मानना है कि पार्टी को भविष्य की राजनीति के लिए युवा नेतृत्व की जरूरत है, जबकि गहलोत समर्थक अनुभव और संगठनात्मक क्षमता को सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2028 तक कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर बहस और तेज हो सकती है। क्योंकि राजस्थान की राजनीति तेजी से बदल रही है। अशोक गहलोत के सामने एक और बड़ी चुनौती उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और पार्टी की भविष्य की जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की है। राजनीतिक गलियारों में अक्सर यह चर्चा होती रही है कि गहलोत केंद्र की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के बजाय राजस्थान की राजनीति में ही बने रहना पसंद करते हैं।

विरासत बनाम वैभव -

अब जब 2028 के चुनाव करीब आते जा रहे तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल होगा कि पार्टी का चेहरा कौन होगा? अशोक गहलोत या नई पीढ़ी का कोई नेता? इन सबके बीच गहलोत की राजनीतिक विरासत को लेकर भी चर्चा होती रही है, जो उनके बेटे वैभव गहलोत की। वैभव गहलोत को राजनीति में स्थापित करने की कई कोशिशें हुईं, लेकिन अब तक उन्हें वैसी सफलता नहीं मिली, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। चुनावी मैदान में मिली हारों ने यह संकेत दिया कि केवल परिवार का नाम किसी नेता को जनता के बीच स्वीकार्यता नहीं दिला सकता। राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाना भी जरूरी होता है।

उभरते नेताओं को तरजीह देना भी जरूरी

यही वजह है कि नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया और जटिल हो जाती है। क्योंकि किसी भी बड़े राजनीतिक दल में समय के साथ युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने और नई पीढ़ी के लिए रास्ता तैयार करने की जरूरत होती है। यदि वरिष्ठ नेता लंबे समय तक प्रदेश की राजनीति के केंद्र में बने रहते हैं, तो उभरते नेताओं के लिए अवसर सीमित हो सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि अनुभव और युवा नेतृत्व के बीच संतुलन बनाने की भी होगी।

गहलोत यदि राजस्थान में सक्रिय रहते हैं, तो उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नई पीढ़ी के नेताओं को पर्याप्त राजनीतिक स्पेस और जिम्मेदारियां मिलें, ताकि भविष्य में नेतृत्व का संक्रमण सहज तरीके से हो सके।

भाजपा का मुद्दा : कांग्रेस की अंदरूनी कलह

गहलोत के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा है। भाजपा लगातार कांग्रेस की अंदरूनी कलह को मुद्दा बनाती रही है। यदि कांग्रेस अपने संगठन को एकजुट नहीं रख पाती, तो इसका सीधा फायदा विपक्ष को मिल सकता है। इस स्थिति में गहलोत को सिर्फ अपनी पार्टी के भीतर ही नहीं, बल्कि विपक्ष के खिलाफ भी मजबूत रणनीति बनानी होगी। इसके अलावा, आने वाले वर्षों में महंगाई, रोजगार, पानी, किसानों की समस्याएं और विकास जैसे मुद्दे चुनावी राजनीति के केंद्र में रहने वाले हैं। जनता अब भावनात्मक नारों से ज्यादा जमीनी कामकाज को महत्व देती है। इसलिए कांग्रेस के किसी भी नेता के लिए सिर्फ लोकप्रियता काफी नहीं होगी, बल्कि परिणाम भी दिखाने होंगे।

सोशल मीडिया से तय होते चुनावी नैरेटिव -

युवा मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है, सोशल मीडिया चुनावी नैरेटिव तय करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है और जनता अब केवल परंपरागत राजनीति से संतुष्ट नहीं दिखती। इसका सीधा मतलब ये है कि गहलोत को अब केवल परंपरागत जनसभाओं या बड़े आयोजनों पर निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि उन्हें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मौजूदगी बढ़ानी होगी। यह मायने रखता है कि वे किस तरह से डिजिटल भाषा, वीडियो और लाइव इंटरैक्शन का इस्तेमाल करके युवाओं से जुड़ते हैं, क्योंकि आज का युवा मतदाता इन्हीं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपने नेता चुनता है।

क्या पायलट को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी?-

राजनीति विश्लेषकों का कहना है कि समय के साथ नेतृत्व बदलता है और नई पीढ़ी अपनी जगह बनाती है। ऐसे में 2028 का चुनाव सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस के भीतर भविष्य के नेतृत्व की दिशा भी तय करेगा। क्या अशोक गहलोत एक बार फिर अपने अनुभव के दम पर पार्टी को नई ताकत देंगे? क्या सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? या फिर कोई तीसरा चेहरा अचानक उभरकर सामने आएगा? बहरहाल इस पर संशय बना हुआ है।

सम्पादकीय

"मानवता सुख शांति प्रेम का, अखिल विश्व में हो
विस्तारस्वतंत्रता का हनन न होवे, रहे सुरक्षित जन अधिकार"

नासूर बना गतिरोध

अमेरिका और ईरान में कोई समझौता होने की संभावनाओं के बीच जिस तरह दोनों किसी सहमति पर भी पहुंचते नहीं दिख रहे हैं, उससे किसी के लिए भी कहना कठिन है कि बातचीत सही दिशा में चल रही है और पश्चिम एशिया संकट शीघ्र समाप्त होने वाला है। पिछले लगभग एक माह से कभी अमेरिका वार्ता के सही दिशा में जारी रहने की घोषणाएं करता है तो कभी ईरान अपने रुख में नरमी दिखाता है, लेकिन परिणाम शून्य है। बीच-बीच में अमेरिका और ईरान, दोनों एक-दूसरे को धमकी भी देते रहते हैं। साफ है कि दोनों का एक-दूसरे के प्रति गहरा अविश्वास है और कथित तौर पर मध्यस्थता कर रहा पाकिस्तान संदेशों का आदान-प्रदान करने के अतिरिक्त और कुछ करने की स्थिति में नहीं। इसका कोई खास मतलब नहीं कि दोनों देशों में युद्धविराम कायम है, क्योंकि वह होर्मुज समुद्री मार्ग बाधित ही है, जिससे विश्व के पांचवें हिस्से की ऊर्जा आपूर्ति होती है। यह आपूर्ति करीब-करीब ठप होने के कारण ऊर्जा संकट गहरा गया है और उसका बुरा असर अमेरिका समेत सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। अब ट्रंप के उन दावों पर भरोसा करना कठिन हो रहा है कि ईरान समझौते के लिए तैयार है। वैसे समझौता न हो पाने के लिए केवल अमेरिका को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ईरान भी इस जिद पर अड़ा है कि वह होर्मुज पर अपना आधिपत्य नहीं छोड़ेगा और अपने संवर्धित यूरेनियम को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। इसका अर्थ है कि वह परमाणु हथियार बनाने के इरादे का परित्याग नहीं करना चाहता। इसे कोई भी नहीं चाहेगा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल करे। उसे न केवल परमाणु हथियार हासिल करने के इरादे को छोड़ना होगा, बल्कि होर्मुज पर नियंत्रण रखने की जिद भी छोड़नी होगी। होर्मुज एक स्वतंत्र समुद्री मार्ग है और ईरान को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह उसे अपनी निजी जागीर समझ ले अथवा वहां से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूले। यह अंतरराष्ट्रीय नियम-कानूनों की अवहेलना करने वाली जिद है। ईरान यह दिखा रहा है कि पश्चिम एशिया संकट जारी रहने से उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, पर सच यह है कि वह आर्थिक तबाही के मुहाने पर है। ऐसे में उसे अपनी जिद छोड़नी चाहिए। बदले में अमेरिका को भी उसे यह भरोसा दिलाना होगा कि उस पर फिर हमला नहीं होगा। दोनों देशों को यह समझना होगा कि उनके बीच का गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। बहुत हो चुका। अब यह गतिरोध टूटना चाहिए, क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों की रोजी-रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र से भी घिरते जा रहे हैं।

> **अमेरिका और ईरान के बीच गतिरोध गहराता जा रहा है, जिससे पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है।**

जवाबदेही का अभाव

नीट प्रकरण की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल सही कहा कि इस परीक्षा के पेपर लीक होने पर जवाबदेही तय हो। यदि ऐसा नहीं होता तो यह दुर्भाग्यपूर्ण ही होगा, क्योंकि नीट के पेपर लीक होने के कारण 22 लाख से अधिक छात्र दोबारा परीक्षा देने के लिए विवश हैं। पेपर लीक के कारण छात्रों को परेशानी उठाने के साथ ही उनके भरोसे को भी ठेस पहुंची है। इसके अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय भी सवालों के घेरे में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कालेजों में प्रवेश की परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी से सीख लेने को भी कहा। कायदे से तो इस नसीहत की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। एनटीए को तो यह सीख स्वत: लेनी चाहिए थी और शिक्षा मंत्रालय को देखना चाहिए था कि ऐसा हो। आखिर इस एजेंसी का गठन ही इसलिए किया गया था, ताकि वह नीर-क्षीर ढंग से परीक्षाएं आयोजित करा सके। यह शर्मनाक है कि इस मामले में एनटीए का रिकार्ड अच्छा नहीं रहा। यह एक तथ्य है कि पहले भी नीट के आयोजन में गड़बड़ी हो चुकी है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। यह निराशाजनक है कि एनटीए के कामकाज में सुधार के लिए गठित राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को प्राथमिकता के आधार पर लागू नहीं किया गया। शायद इसी का दुष्परिणाम रहा कि नीट के पेपर लीक हो गए। आखिर जब राधाकृष्णन समिति ने अक्टूबर 2024 में ही अपनी सिफारिशें सौंप दी थीं तो उन सभी पर दुरुत गति से अमल क्यों नहीं किया गया? इस समिति ने यह पाया था कि एनटीए अपने तमाम काम आउटसोर्स करती है और उसके अधिकांश कर्मचारी संविदा पर हैं। उसने कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं कराने को भी कहा था। समझना कठिन है कि इस स्थिति को बदला क्यों नहीं जा सका? आखिर ऐसी किसी संस्था के गठन का क्या औचित्य, जो अपना काम अपने स्तर पर करने में सक्षम न हो? एनटीए को नीट जैसी परीक्षाएं कराने के लिए अपना तंत्र उसी तरह विकसित करना चाहिए था, जैसे रेल मंत्रालय के आरआईटीईएस यानी राइट्स ने, शहरी विकास मंत्रालय के एनबीसीसी ने, रिजर्व बैंक एवं भारतीय बैंक संघ के तहत एनपीसीआइ ने या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने किया है।

क्या एआई मानवता के महाविनाश का कारण बनेगी?

ललित गर्ग

निश्चित रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बैंकिंग, व्यापार, प्रशासन और संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। रोगों के निदान से लेकर वित्तीय प्रबंधन तक और शिक्षा से लेकर अनुसंधान तक, इसकी उपयोगिता निर्विवाद है। लेकिन हर तकनीकी क्रांति अपने साथ संकट भी लाती है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आज केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं रह गई है, बल्कि वह मानव सभ्यता के भविष्य का निर्णायक मोड़ बनती जा रही है। जिस गति से यह तकनीक विकसित हुई है, उसने दुनिया को आश्चर्यचकित भी किया है और चिंतित भी। अभी तक विज्ञान और तकनीक मनुष्य के हाथों में उपकरण थे, किंतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहली ऐसी शक्ति है जो निर्णय लेने, सीखने, विश्लेषण करने और सृजन करने की क्षमता के साथ स्वयं को निरंतर विकसित कर रही है। यही कारण है कि विश्व के प्रमुख धर्मगुरु, वैज्ञानिक और नीति-निर्माता इसके खतरों को लेकर गंभीर चेतावनियां दे रहे हैं। हाल ही में वर्तमान पोप लियो चौदहवें द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में व्यक्त की गई चिंताएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि युद्ध को नैतिक नहीं बनाया जा सकता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित युद्ध प्रणाली मानवता के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। यह चेतावनी केवल धार्मिक दृष्टि नहीं, बल्कि मानवीय अस्तित्व की रक्षा का प्रश्न है। दुनिया को इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।

पोप ने सामाजिक और वैश्विक मुद्दों पर जारी अपने आधिकारिक संदेश में एआई को मानवता के समक्ष उभरती सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बताया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर चिंता व्यक्त की कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल तकनीकी परिवर्तन का माध्यम नहीं रह गई है, बल्कि यह युद्ध, राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को प्रभावित करने वाली शक्ति बनती जा रही है। उन्होंने दुनिया को चेताया कि तकनीक का उद्देश्य मनुष्य पर प्रभुत्व स्थापित करना नहीं, बल्कि उसकी सेवा करना होना चाहिए। उनका संदेश मानव-केंद्रित विकास की अवधारणा को बल देता है, जिसमें विज्ञान और तकनीक को नैतिकता, मानवीय गरिमा और करुणा के अधीन रखा जाए। पोप की यह चेतावनी केवल धार्मिक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि एक वैश्विक मानवीय आह्वान है कि एआई की अंधी दौड़ में मानवता, संवेदना और नैतिकता का क्षरण न होने दिया जाए। आज जब महाशक्तियां एआई के माध्यम से प्रभाव और नियंत्रण की प्रतिस्पर्धा में लगी हैं, तब पोप का यह संदेश विश्व समुदाय को संयम, उत्तरदायित्व और मानवीय मूल्यों की ओर लौटने का मार्ग दिखाता है। पोप ने स्पष्ट कहा कि कोई भी एल्गोरिद्म युद्ध को नैतिक नहीं बना सकता और तकनीक को मानव विवेक का विकल्प नहीं बनने दिया जा सकता। पोप ने चर्च के सामाजिक सरोकारों से जुड़े अपने इस आधिकारिक पत्र में पहली बार एआई को प्रमुख विषय बनाया, जो इस बात का संकेत है कि इसका प्रभाव केवल तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मानव जीवन, समाज और वैश्विक व्यवस्था को व्यापक रूप से प्रभावित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से एआई आधारित स्वायत्त हथियार प्रणालियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि इस तकनीक को पूर्णत: मानवीय नियंत्रण में नहीं रखा गया तो यह युद्ध, शोषण और दासता के नए रूपों को जन्म दे सकती है। पोप ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को निरस्त्र करने का आह्वान करते हुए उसका आशय तकनीक का विरोध नहीं, बल्कि उसके अनियंत्रित और अमानवीय उपयोग पर रोक लगाना बताया। उनका कहना था कि युद्ध और शांति से जुड़े निर्णय अंतत: नैतिकता, करुणा और विवेक पर आधारित होने चाहिए, उन्हें मशीनों के हवाले नहीं किया जा सकता। आज जब अमेरिका, चीन और अन्य महाशक्तियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता की होड़ में लगी हैं और युद्ध तकनीकों में इसका उपयोग बढ़ रहा है, तब पोप का यह संदेश मानवता के लिए एक नैतिक दिशा-सूचक के रूप में सामने आया है कि तकनीक मनुष्य की सेवक बने, स्वामी नहीं; और विकास का केंद्र मानव गरिमा, संवेदना तथा विश्वशांति ही रहे।

निश्चित रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बैंकिंग, व्यापार, प्रशासन और संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। रोगों के निदान से लेकर वित्तीय प्रबंधन तक और शिक्षा से लेकर अनुसंधान तक, इसकी उपयोगिता निर्विवाद है। लेकिन हर तकनीकी क्रांति अपने साथ संकट भी लाती है। आज वही संकट स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। सबसे बड़ा संकट रोजगार का है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने लाखों लोगों के कार्यों को प्रतिस्थापित करना शुरू कर दिया है। ग्राहक सेवा, लेखन, अनुवाद, लेखांकन, सूचना प्रबंधन, प्रोग्रामिंग और कार्यालयी कार्यों में मनुष्य की आवश्यकता तेजी से घट रही है। मशीनें कम लागत, अधिक गति और निरंतर कार्य क्षमता के कारण मनुष्य का स्थान ले रही हैं। इससे केवल बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, बल्कि सामाजिक असंतुलन और आर्थिक विषमता भी गहराएगी। जिन देशों और कंपनियों के पास कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नियंत्रण होगा, आर्थिक शक्ति भी उन्हीं के हाथों में केंद्रित हो जाएगी। इससे विश्व व्यवस्था में असमानता का नया स्वरूप उभरेगा। इससे भी अधिक गंभीर प्रश्न वैश्विक सुरक्षा का है। आज अमेरिका, चीन और अन्य महाशक्तियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता की होड़ में लगी हुई हैं। यह प्रतिस्पर्धा केवल तकनीकी श्रेष्ठता तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक प्रभुत्व का नया संघर्ष बन चुकी है। जैसे कभी परमाणु हथियारों और घातक अस्त्र-शस्त्रों के माध्यम से शक्ति संतुलन स्थापित हुआ था, वैसे ही अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता भविष्य की सामरिक शक्ति बन रही है। स्वायत्त हथियार प्रणाली, बुद्धिमान ड्रोन और बिना मानवीय हस्तक्षेप के निर्णय लेने वाली युद्ध तकनीकें मानवता के लिए भयावह संकेत हैं। यदि युद्ध का निर्णय मशीनों के हाथों में चला गया तो संवेदना, विवेक और नैतिकता समाप्त हो जाएगी। मशीनों के लिए मानव जीवन केवल आंकड़े होंगे। ऐसी स्थिति महाविनाश की संभावना को जन्म दे सकती है। पोप की यह चेतावनी इसी संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है कि युद्ध का अंतिम निर्णय मानव विवेक के अधीन रहना चाहिए। साइबर सुरक्षा भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण नई चुनौतियों से घिर गई है। बैंकिंग व्यवस्था, विद्युत तंत्र, रक्षा नेटवर्क और संचार प्रणाली आज डिजिटल माध्यमों पर निर्भर हैं। एआई आधारित साइबर हमले किसी भी राष्ट्र को कुछ घंटों में अस्थिर कर सकते हैं। झूठे संदेश, भ्रामक वीडियो, कृत्रिम चित्र और आवाजों के माध्यम से सामाजिक तनाव उत्पन्न किए जा सकते हैं।

कर्नाटक में बदलाव के बाद की चुनौतियां

संजय गुप्त

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के त्यागपत्र देने के साथ ही उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के राज्य की कमान संभालने का रास्ता साफ हो गया। इससे शिवकुमार की तो चाहत पूरी हो गई, लेकिन यह कहना कठिन है कि कर्नाटक कांग्रेस में सब कुछ सामान्य होने जा रहा है या फिर राज्य की विभिन्न समस्याओं के समाधान की राह आसान हो गई है। सिद्दरमैया ने त्यागपत्र देने की घोषणा करते हुए यह कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने जैसा कहा, मैंने वैसा किया, लेकिन उन्होंने राज्यसभा आकर कांग्रेस की केंद्रीय स्तर की राजनीति में सक्रिय होने का आग्रह ठुकराते हुए कहा कि वे राज्य की राजनीति में ही सक्रिय रहेंगे। चूंकि सिद्दरमैया जमीनी स्तर की राजनीति करने वाले नेता हैं और उनका अपना जनाधार है, इसलिए वे मुख्यमंत्री बनने जा रहे शिवकुमार के लिए चुनौती खड़ी कर सकते हैं। इसके नतीजे में वहां नए सिरे से गुटबाजी भी पनप सकती है, क्योंकि शिवकुमार के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल से सिद्दरमैया के कुछ समर्थक बाहर हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह स्वाभाविक ही है कि शिवकुमार अपने हिसाब से शासन से चलाएंगे और इसके लिए वे प्रशासन में भी पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थकों को किनारे कर सकते हैं। इसके आसार कम ही हैं कि सिद्दरमैया अपने उत्तराधिकारी शिवकुमार के लिए खुला मैदान छोड़ेंगे, क्योंकि जमीनी राजनीति करने वाला कोई नेता अपना राजनीतिक वर्चस्व इतनी आसानी से नहीं छोड़ता।

अपने देश में तो ऐसा और भी कम होता है। अपने यहां उम्रदराज नेता तब तक राजनीति से रिटायर ही नहीं होते, जब तक उन्हें बिल्कुल किनारे न कर दिया जाए। कांग्रेस सिद्दरमैया की उपेक्षा करने का जोखिम नहीं उठा सकती। शिवकुमार 2023 में तभी से मुख्यमंत्री पद के आकांक्षी थे, जब कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने वरिष्ठता के आधार पर सिद्दरमैया का चयन किया। शिवकुमार का दावा था कि उनके और सिद्दरमैया के बीच इसे लेकर सहमति कायम हुई थी कि दोनों ढाई-ढाई वर्ष तक सत्ता संभालेंगे। अपने इस दावे के अनुरूप वे पिछले काफी समय से मुख्यमंत्री पद हासिल करने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन सिद्दरमैया पद छोड़ने को तैयार नहीं थे। आखिरकार कांग्रेस आलाकमान के दबाव में वे तीन वर्ष बाद

> **सिद्दरमैया के त्यागपत्र के बाद डीके शिवकुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे, पर राज्य में गुटबाजी और समस्याओं का सामना करना होगा।**

मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार हुए। स्पष्ट है कि उन्होंने मजबूरी में पद छोड़ा। कर्नाटक की तरह एक समय राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच भी इसे लेकर खींचतना हुई थी कि दोनों के बाच ढाई-ढाई साल तक मुख्यमंत्री बनने की सहमति बनी थी। सचिन पायलट ने बहुत कोशिश की कि इस कथित सहमति के आधार पर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिले, लेकिन अशोक गहलोत टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान के निर्देशों को भी ठुकरा दिया। इस कारण सचिन पायलट एवं उनके बीच खींचतान जारी रही और कांग्रेस आलाकमान अंत समय तक कोई फैसला नहीं कर सका। ऐसा ही छत्तीसगढ़ में हुआ। यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंह देव के बीच इसे लेकर झगड़ा होता रहा कि ढाई-ढाई साल तक सत्ता संभालने की बात हुई थी। यहां भी कांग्रेस नेतृत्व कोई फैसला नहीं कर सका। नतीजा यह हुआ कि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की पराजय का एक कारण मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए खींचतान भी बनी। कांग्रेस नेतृत्व ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को विधानसभा चुनाव के करीब एक वर्ष पहले मुख्यमंत्री पद से हटने के लिए बाध्य किया, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके बजाय चरणजीत सिंह चन्नी को मिली। इसके चलते गुटबाजी को बढ़ावा मिला और विधानसभा चुनावों में इसका लाभ आम आदमी पार्टी ने उठाया। कर्नाटक में दो वर्ष बाद चुनाव होने हैं। कहना कठिन है कि तब क्या होगा, लेकिन यह ध्यान रहे कि कर्नाटक में 1980 के बाद कोई भी सरकार सत्ता में नहीं लौटी है। शिवकुमार इस सिलसिले को तोड़ सकेंगे, यह कहना इसलिए कठिन है, क्योंकि कर्नाटक कई समस्याओं से घिरा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु आइटी सिटी के रूप में विख्यात है, लेकिन इस समय बेंगलुरु के साथ देश भर का आइटी उद्योग समस्याओं से घिरा है। कर्नाटक में बेंगलुरु को छोड़कर एक दो शहर ही सही तरह विकसित हो पाए हैं। बेंगलुरु और शेष राज्य में जो आर्थिक असमानता दिखती है, वह यही बताती है कि सरकारों ने अन्य शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। कर्नाटक उसी तरह की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे अन्य कई राज्य। किसी भी दल के लिए कर्नाटक के लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना इसलिए कठिन होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की जनता को संतुष्टि के नाम पर विकास के काम कम, लोकलुभावन योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यह किसी से छिपा नहीं कि रेवड़ी राजनीति कर्नाटक के लिए एक समस्या बन गई है। लोकलुभावन योजनाएं पूरी करने के फेर में राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। ऐसी योजनाओं से एक तो मुफ्तखोरी की संस्कृति पनपती है और दूसरे राज्य की वित्तीय सेहत बिगड़ती है। ऐसा कुछ अन्य राज्यों में भी हो रहा है। कर्नाटक की तरह कई राज्यों में आर्थिक विकास राजधानी और चुनिंदा शहरों में ही केंद्रित दिखता है। अधिकांश राज्यों के पिछड़ेपन का कारण यही है कि वहां की सरकारें प्रदेश के समग्र विकास पर ध्यान नहीं देतीं। इससे आर्थिक असंतुलन और असमानता बढ़ती है। यह कर्नाटक में भी देखने को मिल रहा है। यह स्थिति शिवकुमार के लिए चुनौती बन सकती है। प्रमुख राज्यों में देखा जाए तो कांग्रेस के पास तेलंगाना को छोड़कर कर्नाटक ही बचा है। यदि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ से राज्य की सत्ता निकल गई और भाजपा सत्ता में आ गई तो उसका देशव्यापी प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। इसी के साथ कांग्रेस के लिए उसका मुकाबला करना कठिन हो जाएगा। स्पष्ट है कि शिवकुमार का मुख्यमंत्री बनना तो तय हो गया, लेकिन उनके लिए राज्य को समस्याओं से उबार पाना आसान नहीं होने वाला।

समस्या को 'पहेली' की तरह देखें

चिंता तब बढ़ती है, जब हम समस्या को अंतिम परिणति मान लेते हैं। शांत दिमाग से सोचें, तो वह परेशानी एक हल होने वाली पहेली लगती है। कई बार समाधान की शुरुआत सोच बदलने से ही शुरू हो जाती है।

मेरे पिताजी हर स्थिति में सबसे बुरे की कल्पना कर लेते हैं, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक। थेरेपिस्ट सोचने के इस तरीके को कैटास्ट्रोफाइजिंग (हर बात की सबसे बुरी कल्पना करना) कहते हैं। पिताजी घर आने पर हर चीज की बारीकी से जांच करते हुए गंभीर अंदाज में चेतावनी देते हैं। उनका एक पसंदीदा जुमला है, 'यह तुम्हारा अंत साबित होगा।' तनाव में मेरी भी चिंताएं बढ़ने लगती हैं, लेकिन मैं उन पर काबू पाने के लिए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉ. मार्टिन सेलिगमैन का तरीका अपनाती हूं। डॉ. मार्टिन सेलिगमैन ने जीवन की कठिनाइयों को समझने के लिए तीन महत्वपूर्ण पहलू बताए हैं, स्थायित्व, व्यापकता और नियंत्रण क्षमता। दरअसल, हमारा दिमाग सकारात्मक घटनाओं की तुलना में नकारात्मक घटनाओं पर ज्यादा ध्यान देता है। इसलिए, परेशानियां लंबे समय तक याद रहती हैं और लगता है कि वे कभी खत्म ही नहीं होंगी। हाउ ए लिटल बिकम्स ए लॉट के लेखक एरिक जिमर कहते हैं कि कई बार एक गलती या बुरा अनुभव हमें महसूस कराता है कि हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि मुश्किल वक्त में हम परेशानी पर इतना ध्यान देते हैं कि वह जटिल दिखाई देने लगती है, जबकि जरूरी यह है कि हम थोड़ा पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखें। इस संदर्भ में, जिमर ने अपना उदाहरण देते हुए ?बताया कि पहले उनका व्यवसाय था, जो बाद में बंद हो गया। ऐसे में, उन्हें लगने लगा कि वह असफल इन्सान हैं। पर, जब उन्होंने खुद से पूछा कि क्या इससे उनका जीवन असफल हो गया, तो उन्हें एहसास हुआ कि असफल तो व्यवसाय हुआ है, न कि वह खुद। डॉ. सेलिगमैन भी कहते हैं कि किसी कठिन परिस्थिति को स्वीकार करने के बाद खुद से पूछना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं? इसलिए, जो चीजें आपके नियंत्रण में हैं, उन्हें पहचानिए। ज्यादातर स्थितियों में कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है, जिसे आप ढूंढ सकते हैं। वहीं, जिमर कहते हैं कि किसी चुनौती को 'पहेली' की तरह देखें। इससे दिमाग को एहसास होता है कि उस समस्या का हल जरूर होगा, बस उसे खोजने की जरूरत है। तनाव और चिंताओं से पूरी तरह बचना संभव नहीं है, लेकिन सही नजरिया अपनाकर हम इन्हें अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। यदि हम खुद से सही सवाल पूछें, तो समझ सकते हैं कि कौन-सी चिंता वास्तव में गंभीर है और कौन केवल दिमागी डर। कई बार समाधान की शुरुआत सोच बदलने से ही शुरू हो जाती है।

नई शुभ्रता की आशाओं में अतीत का आकाश

हिंदी के लिए 30 मई का दिन ऐतिहासिक था। इस दिन हिंदी पत्रकारिता ने अपनी दो सौ साल की यात्रा पूरी कर ली है। हिंदी पत्रकारिता की एक विशेषता रही है। अन्य राज्यों और भाषाओं की पत्रकारिता की तरह उसकी शुरुआत अपने राज्य नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में हुई। बहुत दिनों तक बहस चलती रही कि हिंदी का पहला अखबार कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र निश्चित तौर पर हिंदी के उन्नायक रहे हैं। बहुत दिनों तक कहा जाता रहा कि उनके द्वारा संपादित बनारस अखबार हिंदी का पहला अखबार है। लंबी बहस के बाद तय हुआ कि कलकत्ता से 30 मई, 1826 को निकला उदन्त मार्त्तण्ड हिंदी का पहला पत्र है। हिंदी के पहले अखबार के रूप में उदन्त मार्त्तण्ड को स्वीकृति दिलाने का श्रेय बंगाल के बुद्धिजीवी ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय को है। उन्होंने मई, 1931 के अंक में कलकत्ता से प्रकाशित विशाल भारत में 'हिंदी पत्रों की आरंभिक कथा' शीर्षक एक लेख लिखा था, इसी में उन्होंने उदन्त मार्त्तण्ड को हिंदी का पहला समाचार पत्र बताया था। इस लेख के साथ उदन्त मार्त्तण्ड के प्रवेशांक का चित्र भी प्रकाशित हुआ था। इसके प्रकाशक, संपादक और मालिक कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे, जो पेशे से वकील थे। उन्होंने जिस साहस के साथ उदन्त मार्त्तण्ड का प्रकाशन शुरू किया, वह सराहनीय है। हालांकि इसके केवल 79 अंक ही निकल सके और 1827 में वह बंद हो गया। लेकिन उन्होंने हिंदी पत्रकारिता की जो साहसपूर्ण कहानी शुरू की, उसी की बुनियाद पर आगे बढ़ते हुए हिंदी पत्रकारिता ने दो सौ साल का संघर्षपूर्ण और गौरवशाली सफर पूरा किया है। उस दौर में संपादक पर ही सारा दारोमदार था। तब हिंदी भी विकसित हो रही थी। शुक्ल जी उदन्त मार्त्तण्ड के सब कुछ थे। क्या लिखा जाए, किसे संबोधित किया जाए, वे ही

तय करते थे। जिस दौर में उदन्त मार्त्तण्ड निकला, उस दौर में अंग्रेजों ने तय कर रखा था कि हिंदीभाषी क्षेत्रों को कुछ न दिया जाए। भाषायी पत्रों को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने बाद में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया। लेकिन इसका ठीक उलटा हुआ। उस दौर में समाचार पत्रों ने उग्र राष्ट्रीयता का समर्थन किया। उसी दौर में राजा राममोहन राय ने राष्ट्रीयता को सुर दिया और यह सुर भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर महात्मा गांधी के छा जाने तक बरकरार रहा। हिंदी पत्रकारिता की कहानी, हिंदी भाषा के विकास और राष्ट्रीयता के विकास भी गाथा है। हिंदी पत्रकारिता ने जातीय चेतना जगाने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। बेशक उदन्त मार्त्तण्ड कलकत्ता से निकला, लेकिन उन्नीसवीं सदी के आखिर तक आते-आते हिंदी पत्रकारिता के दो प्रमुख केंद्र उभरे, पहला कलकत्ता और दूसरा बनारस। इसी दौर में कलकत्ता से ही पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी के संपादन में भारत मित्र निकला। तब संपादकों को कई जगह अपने पत्रों में छपी सामग्री को ग्राहकों को पढ़कर सुनाना पड़ता था। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने भारत मित्र के पहले संपादकीय में लिखा है, 'समाचार पत्र प्रजा का प्रतिनिधि स्वरूप होता है। मुख्य तौर पर हृदय में संस्कार उत्पन्न करने में समाचार पत्र जितना समर्थ है, दूसरी कोई और विधा नहीं है।' ऐसी टिप्पणियां उस दौर के पत्रों में मिलती हैं। एक और समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण का 'उन्नीसवीं शताब्दी और ये सभ्यता' शीर्षक संपादकीय दृष्टव्य है, 'क्या इसी को सभ्यता, राजनीति, धर्मनीति और दयावृत्ति कहते हैं? जो लोग अपनी सभ्यता, राजनीति और दयावृत्ति के आगे प्राचीनों को असभ्य, मूर्ख, धर्मज्ञान शून्य और नृशंस कहते हैं, उन्हीं लोगों का ये काम है?' उसी दौर के एक और पत्र उचित वक्ता के संपादकीय में संपादक दुर्गाप्रसाद मिश्र सलाह देते हैं, 'देसी पत्र संपादको, सावधान, कहीं जले का नाम सुनकर कर्तव्यविमूढ़ मत हो जाना। यदि धर्म की रक्षा करते हुए, गवर्नमेंट को सत्परामर्श देते हुए जेल भी जाना पड़े, क्या चिंता है। मानहानि नहीं होनी है।'

उदन्त से मार्तण्ड तक: पत्रकारिता का ध्येय केवल सूचना नहीं, समाज में प्रकाश भी

संस्कृत भाषा में 'उदन्त' शब्द का मूल अर्थ है- संपूर्ण समाचार, वार्ता, प्रवृत्ति, वृत्तांत या पूर्ण जानकारी। संस्कृत के अमरकोष और मेदिनिकोश के साथ ही मोनियर-विलियम्स द्वारा 1851 में संपादित संस्कृत-अंग्रेजी शब्दकोश में 'उदन्त' को समाचार, बुद्धिमत्ता, पूर्ण विवरण और शुभ सूचना के अर्थ में ग्रहण किया गया है। महाकवि कालिदास के मेघदूत में 'कान्तोदन्त:' तथा रघुवंश में 'प्रियोदन्तम' जैसे प्रयोग सिद्ध करते हैं कि 'उदन्त' केवल सूचना नहीं, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक संवाद का माध्यम है।

संस्कृत के व्याकरण के अनुसार 'उदन्त' शब्द की व्युत्पत्ति 'उद्गत: अन्त: यस्मात' मानी गई है। तात्पर्य है कि वह जिससे किसी घटना का पूरा निष्कर्ष या संपूर्ण विवरण प्रकट हो जाए। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय परंपरा में 'उदन्त' केवल खबर नहीं, बल्कि प्रामाणिक वृत्तांत माना जाता था। आधुनिक पत्रकारिता का मूल तत्व भी यही होना चाहिए। संस्कृत भाषा में समाचार शब्द उस अर्थ में नहीं बनता, जिसमें प्राय: उसका प्रयोग किया जाता है।

यही कारण है कि पिछले पांच दशकों से आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले संस्कृत समाचारों का आरंभ 'संप्रति वार्ता: श्रूयन्तां' से होता है, क्योंकि संस्कृत में न्यूज के लिए वार्ता, प्रवृत्ति, वृत्तांत और उदन्त जैसे शब्द उपलब्ध हैं।

जब हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का नाम उदन्त मार्तण्ड रखा गया, तब उसमें गहन सांस्कृतिक प्रतीक छिपा था। इसका सांस्कृतिक संबंध संस्कृत भाषा से जोड़ा गया। उदन्त और मार्त्तण्ड, दोनों शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। मार्त्तण्ड का अर्थ सूर्य है। इस प्रकार उदन्त मार्त्तण्ड का आशय हुआ- समाचार-सूर्य या समाचारों का प्रकाश फैलाने वाला। यह नाम भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक जनसंचार के अद्भुत समन्वय का उदाहरण है।

हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी पर उदन्त शब्द हमें स्मरण कराता है कि पत्रकारिता का ध्येय केवल सूचना देना नहीं, बल्कि समाज को प्रकाश देना भी है, ठीक उसी प्रकार जैसे मार्तण्ड संपूर्ण जगत को आलोकित करता है।

आज ही किचन से बाहर निकालकर फेंक दें ये 5 चीजें

किचन सिर्फ भूख मिटाने की जगह नहीं है, बल्कि यह हमारे घर में सेहत का मंदिर भी है. लेकिन, फैशन के नाम पर हम एल्युमिनियम, प्लास्टिक और नॉन-स्टिक कोटेड बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे शरीर को जहर दे रहे हैं. हमारे पुरखों के इस्तेमाल किए गए मिट्टी और लोहे के बर्तनों की जगह हम रंगीन प्लास्टिक के बर्तन पसंद करके, हम अनजाने में खुद के लिए कई परेशानियां खड़ी कर रहे हैं. इन बर्तनों से निकलने वाले टॉक्सिन खाने को खराब कर देते हैं और इस तरह धीरे-धीरे हमारी सेहत को कमजोर करते हैं

हमारा किचन एक लैबोरेटरी की तरह है. हम इसमें मौजूद वस्तुओं और सामग्रियों के साथ लगातार प्रयोग करते रहते हैं. इस प्रोसेस में, सुविधा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नॉन-स्टिक पैन पर लगी टेफ्लॉन कोटिंग ज्यादा तापमान के संपर्क में आने पर जहरीली गैसें छोड़ती है और हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण बनती है. इसके अलावा, नेशनल हेल्थ रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह बताया गया है कि प्लास्टिक के बर्तनों में गर्म चीजें रखने से माइक्रोप्लास्टिक के कण भोजन में मिल सकते हैं, जिससे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां होने का खतरा पैदा हो सकता है.

वहीं, एक वेबसाइट पर छपी एक स्टडी में कहा गया है कि एल्युमीनियम के बर्तनों में खाना पकाने से खाने में मेटल के छोटे-छोटे कण आ सकते हैं और इससे नर्वस सिस्टम पर असर पड़ सकता है. इसके अलावा, आजकल हम जो माइक्रोवेव ओवन के प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करते हैं और सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले हार्ड केमिकल क्लीनर सांस और पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं. खाना पकाने के बर्तनों से लेकर खाना स्टोर करने के तरीकों तक, छोटी-छोटी गलतियां लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों की

वजह बन सकती हैं. इसलिए, किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजों की क्वालिटी और उनके असर के बारे में पता होना जरूरी है. मिट्टी, पीतल और स्टील के बर्तन, जो जितना हो सके नेचर के करीब हों, इस्तेमाल करने से हमारी सेहत सुरक्षित रहेगी. इस बारे में, आइए जानें हमारे कमरों में मौजूद नुकसानदायक चीजों, उनसे होने वाले नुकसान और उनके विकल्पों के बारे में...

प्लास्टिक की चीजें और कटिंग बोर्ड

हमारे किचन में आधी चीजें प्लास्टिक की बनी होती हैं. जब गर्म खाना प्लास्टिक के कंटेनर में रखा जाता है या प्लास्टिक के चम्मच इस्तेमाल किए जाते हैं, तो [illegible] (बिस्फेनॉल [illegible]) जैसे नुकसानदायक केमिकल खाने में मिल जाते हैं. इसी तरह, जब सब्जियां प्लास्टिक के कटिंग बोर्ड पर काटी जाती हैं, तो प्लास्टिक के छोटे-छोटे कण खाने में चले जाते हैं. इसलिए, इन कणों के शरीर में जाने का खतरा रहता है. इसलिए, प्लास्टिक की चीजों के बजाय कांच, स्टेनलेस स्टील या लकड़ी से बनी चीजों का इस्तेमाल करना बेहतर है.

खरोंच वाले नॉन-स्टिक पैन

जब नॉन-स्टिक कुकवेयर पर टेफ्लॉन कोटिंग पर खरोंच लग जाती है या वह ज्यादा तापमान के संपर्क में आता है, तो उससे पीएफएएस नाम की जहरीली गैस निकलती है. समय के साथ, ये गैसें हार्मोनल असंतुलन और कई बीमारियों का कारण बन सकती हैं. इसलिए, नॉन-स्टिक कोटिंग के खराब हो जाने के बाद ऐसे कुकवेयर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इसकी जगह स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करना बेहतर विकल्प है.

एल्युमिनियम कुकवेयर और फॉइल

एल्युमिनियम, स्वभाव से, एक रिएक्टिव मेटल है. खासकर जब एसिडिक खाने की चीजें जैसे नींबू का रस, टमाटर, या इमली एल्युमिनियम के बर्तनों में पकाई जाती हैं या एल्युमिनियम फॉइल में लपेटी जाती हैं, तो मेटल के कण खाने में मिल सकते हैं और सेहत के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं. इसलिए, एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल करने के बजाय स्टेनलेस स्टील या मिट्टी के कुकवेयर चुनना सही रहता है.

खाना पकाने के बाद बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल होने वाले स्पॉन्ज लगातार गीले रहते हैं, जिससे ऐसा माहौल बनता है जहां ई. कोलाई या साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया पनप सकते हैं। इसलिए, इन स्पॉन्ज को रेगुलर गर्म पानी में भिगोकर साफ करना चाहिए. इन्हें कम से कम हर 15 दिन में बदलना सबसे अच्छा है, या फिर सिलिकॉन स्क्रबर का इस्तेमाल करें.

मेलामाइन टेबलवेयर

आजकल, बहुत से लोग मेलामाइन टेबलवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं. जब इन बर्तनों में गर्म खाना या सूप रखा जाता है, तो इनमें मौजूद केमिकल खाने में मिल सकते हैं. इसलिए, इसके बजाय कांच या सिरेमिक के बर्तन और प्लेट इस्तेमाल करना बेहतर है.

सिर्फ 10 रुपए की छाछ से डैंड्रफ और खुजली होगी छूमंतर, जानिए बालों में इसे लगाने का सही तरीका

आजकल बाल झड़ना आम समस्या बन चुकी है। जिससे महिलाओं से लेकर पुरुष तक परेशान हैं लेकिन टेंशन तब बढ़ जाती है जब बाल तेजी से और हर मौसम में झड़ने लगते हैं। इन समस्याओं के लिए लोग महंगे शैंपू और ट्रीटमेंट पर काफी पैसा खर्च करते हैं, लेकिन बालों की देखभाल के लिए छाछ को एक आसान और असरदार विकल्प माना जाता है। छाछ में मौजूद पोषक तत्व स्कैल्प को साफ रखने और बालों की कई समस्याओं को कम करने में मदद कर सकते हैं।

छाछ बालों के लिए वरदान

आयुर्वेद विशेषज्ञों के मुताबिक, छाछ में लैक्टिक एसिड, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी और अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। लैक्टिक एसिड एक प्राकृतिक क्लींजर की तरह काम करता है। यह स्कैल्प पर जमी गंदगी, अतिरिक्त तेल और मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है। जब स्कैल्प साफ रहती है, तो बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन और पोषण बेहतर तरीके से पहुंच पाता है। इससे स्कैल्प ज्यादा साफ होती है।

डैंड्रफ और खुजली की समस्या में भी छाछ काफी मददगार

डैंड्रफ और खुजली की समस्या में भी छाछ काफी मददगार मानी जाती है। कई बार स्कैल्प पर फंगल संक्रमण या गंदगी जमा होने की वजह से खुजली और सफेद परत बनने लगती है। छाछ में मौजूद प्राकृतिक एसिड और प्रोबायोटिक तत्व स्कैल्प का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। इससे फंगल संक्रमण कम होता है और खुजली से राहत मिलती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर सप्ताह में एक या दो बार छाछ का इस्तेमाल किया जाए, तो धीरे-धीरे डैंड्रफ की समस्या कम होने लगती है।

सूखे और बेजान बालों के लिए फायदेमंद

आयुर्वेद विशेषज्ञों की मानें तो, सूखे और बेजान बालों के लिए भी छाछ को फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद प्रोटीन और फैट बालों को प्राकृतिक नमी देने में मदद करते हैं। यही वजह है कि छाछ बालों पर एक प्राकृतिक कंडीशनर की तरह काम करती है।

जब बालों में नमी बनी रहती है तो वे ज्यादा मुलायम और चमकदार बनते हैं। खासकर गर्मियों में धूप और पसीने की वजह से बाल जल्दी रूखे हो जाते हैं। ऐसे में छाछ स्कैल्प को ठंडक पहुंचाने का भी काम करती है।

बालों में छाछ लगाने का क्या है सही तरीका ?

एक्सपर्ट्स बताते है कि, बालों में छाछ लगाने का तरीका भी बेहद आसान है। सबसे पहले ताजी छाछ लें। इसके बाद इसे हाथों या कॉटन की मदद से स्कैल्प और बालों की लंबाई पर अच्छे से लगाएं। लगभग 20 से 30 मिनट तक इसे बालों में लगा रहने दें ताकि इसके पोषक तत्व स्कैल्प तक पहुंच सकें। इसके बाद हल्के शैंपू से बाल धो लें।

टैटू से हो सकता है संक्रमण

आजकल युवाओं में टैटू बनाना फैशन के साथ ही स्टेटस सिंबल भी बनता जा रहा है पर क्या आपके इसके खतरे जानते हैं।

टैटू का शौक रखते हैं और नया-नया टैटू बनवाया है तो इसकी खास देखभाल करना भी बहुत जरूरी है। खासकर 24 घंटे तो इसकी विशेष देखभाल जरूरी है। टैटू आर्टिस्ट भी सलाह देते हैं कि टैटू गुदबाते समय बैक्टिरियल संक्रमण से बचाना बहुत जरूरी है। इनके अनुसार टैटू बनवाने के बाद कई सावधानियों का ध्यान जरूर रखना चाहिए।

24 घंटे तक इस पर पट्टी बंधी होनी चाहिए क्योंकि इतने पर तक इस पर बैक्टैरियल इंफेक्शन हो सकता है। इसलिए टैटू वाली सतह को धूल और हर तरह के इंफेक्शन से बचाने की जरूरत है।

24 घंटे बाद पट्टी हटाने के बाद हल्के ठंडे या गुनगुने पानी से टैटू एरिया को धोना चाहिए। इसे बिल्कुल भी न खरोंचें किसी भी तरह की सक्रैचिंग करने से बचें। अगर 24 घंटे बाद इसमें कुजली होती है तो डॉक्टर को दिखाएं।

पहले तीन दिन तक इसमें प्रोएक्टिव ऑइनमेंट लगाएं। इसके अलावा लोशन और माइश्चराइजर लगाने से भी बचें।

टैटू वाले एरिया पर खुशबू वाला लोशन लगाने से बचें, क्योंकि इसमें अल्कोहल होता है।

इसके अलावा इसे धूप से बचाकर रखें, क्योंकि धूप से टैटू का रंग कमजोर हो जाता है।

फिट रहने के लिए जिम की जरूरत नहीं, बस रोज सीढ़ियां चढ़ने की आदत डाले, मिलेंगे ढेरों फायदे

आजकल होटल हो, ऑफिस हो या फिर शॉपिंग मॉल हम में से ज्यादातर लोग आने-जाने के लिए सीढ़ियों की बजाय लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। सामने सीढ़ियों का विकल्प मौजूद होते हुए भी हम लिफ्ट के इंतजार में खड़े रहते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ के अनुसार,अगर आप भी ऐसे लोगों की कैटेगरी में आते हैं तो आज से सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि इसके एक दो नहीं अनेक फायदे हैं। ऐसे में आइए जान लीजिए सीढ़ियां चढ़ने से सेहत को कौन-कौन से फायदे हो सकते हैं।

सीढ़ियाँ चढ़ना इतना असरदार व्यायाम क्यों है?

सीढ़ियाँ चढ़ना कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मिलाजुला रूप है हर सीढ़ी आपके ग्लूट्स, क्वाड्स, काफ्स और कोर मसल्स को सक्रिय करती है, जिससे हृदय गति बढ़ती है। थोड़े समय के लिए भी सीढ़ियाँ चढ़ने से कार्डियोवस्कुलर फिटनेस में सुधार होता है, निचले शरीर की ताकत बढ़ती है और कैलोरी बर्न होती है।

पैरों की मांसपेशियां मजबूत

सीढ़ियां चढ़ने के एक नहीं कई फायदे हैं। सीढ़ियां चढ़ना एक बेहतरीन व्यायाम है, जो बिना किसी उपकरण के किया जा सकता है। इससे पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वजन नियंत्रण में रहता है और शरीर की सहनशक्ति बढ़ती है।

ब्लड प्रेशर कंट्रोल

नियमित रूप से सीढ़ियां चढ़ने से हृदय स्वस्थ रहता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी संतुलित रहता है। इसके अलावा यह आदत पूरे दिन ऊर्जा से भर देती है। सुबह ऑफिस या घर में सीढ़ियां चढ़कर शुरू किया गया दिन ज्यादा सक्रिय और तरोताजा रहता है।

तनाव कम व मूड बेहतर

विशेषज्ञों का कहना है कि 'एक्टिव बॉडी' बनाए रखने के लिए ऐसी छोटी आदतें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस छोटी सी आदत से बेहतर हार्ट हेल्थ होती है, ज्यादा एनर्जी और स्फूर्ति मिलती है, पैर और हड्डियां मजबूत होती हैं। वजन नियंत्रण में रहता है, सांस संबंधित समस्याएं दूर होती हैं और तनाव कम व मूड बेहतर होता है।

एनएचएम ने लोगों से अपील की है कि जहां भी संभव हो, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। अगर ऑफिस की मंजिल ज्यादा ऊंची है तो कम से कम कुछ मंजिलें सीढ़ियों से चढ़कर शुरू करें। धीरे-धीरे इस आदत को बढ़ाया जा सकता है।

मोदी का एक फोन कॉल

...और बदल गई मदन राठौड़ की किस्मत !

हाशिये से लेकर बागी नेता तक कठिनाईयों से भरा रहा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ का राजनीतिक सफर

करिअर को खत्म करने पर तुले थे विरोधी

नीरज मेहरा। जयपुर

राजनीति में कई बार एक फैसला जिंदगी बदल देता है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा नेता भी है जिसकी किस्मत सिर्फ एक फोन कॉल ने बदल दी। एक समय ऐसा था जब अपनी ही पार्टी में उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था। टिकट कट चुका था। समर्थकों में नाराजगी थी और उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल भी फूंक दिया था। निर्दलीय पर्चा भरा, इसी बीच खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके पास फोन आया। पीएम मोदी ने फोन पर सिर्फ एक लाइन कही 'जाओ और अपना नामांकन वापस ले लो '। पीएम के इस एक फोन कॉल का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने तुरंत बिना कोई सवाल किए अपना पर्चा वापस ले लिया और पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के लिए प्रचार में जुट गए। फिर किस्मत ने लिया यू-टर्न। पार्टी के प्रति इस निष्ठा और अनुशासन का इनाम उन्हें जल्द ही मिला। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि असल हकीकत है मदन राठौड़ की। फरवरी 2024 में भाजपा ने उन्हें राजस्थान से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया और वे निर्विरोध चुनकर संसद पहुंचे। जुलाई 2024 में संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए भाजपा आलाकमान ने उन्हें सीपी जोशी की जगह राजस्थान भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया।

निर्दलीय ठोक चुके थे ताल -

भाजपा नेता मदन राठौड़ ने वर्ष 2023 में सुमेरपुर विधानसभा सीट से बीजेपी का टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने यहां से जोराराम कुमावत को दूसरी बार टिकट दे दिया। टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर मदन राठौड़ निर्दलीय ही चुनाव मैदान में कूद गए। चुनाव में नामांकन भरा। मदन राठौड़ अपनी ही पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार जोराराम कुमावत की हार का बड़ा कारण बन सकते थे। ये सोचकर राजस्थान के नेताओं ने पीएम मोदी तक ये बात पहुंचाई।

फिर सुमेरपुर सीट बनीं मूंछ का सवाल

मदन राठौड़ ने पीएम मोदी से हुई बात के बाद नामांकन फार्म वापस ले लिया और प्रचार में जुट गए, बगैर किसी लाग-लपेट और नफा-नुकसान का सोचे। फिर क्या था.. परिणाम आया और बीजेपी जीत गई। लेकिन अब आपको बताते है फोन के पीछे की असली कहानी। आपको लग रहा होगा कि क्या मदन राठौड़ इतने बड़े नेता थे कि उनके पास सीधा पीएम मोदी का फोन आए और उनसे निवेदन करे कि जोराराम कुमावत को जिताने के लिए नाम वापस ले लो।

पीएमओ से बजी फोन की घंटी -

इधर मदन राठौड अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार में जुटे थे कि अचानक मोबाइल की घंटी बजी, फोन था सीधा पीएमओ से। फोन देखकर पहले मदन राठौड़ चौंके। लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही फोन उठाया उधर से आवाज आई मदन जी बोल रहे हैं। साहब बात करेंगे, यकायक मदन राठौड़ को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उधर से आवाज आई नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं। बस फिर क्या था मदन राठौड़ ने मोदी जी को प्रणाम किया और अपनी पीड़ा बताई। मोदी जी ने पुरी बात सुनी और कहा आप पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है। आपका सम्मान रखा जाएगा। आप पर्चा उठाए और आप पार्टी के लिए काम करें। बाकी हम पर छोड़ दें। बस मोदीजी के इस फोन ने मदन राठौड़ की जिंदगी बदल कर रख दी। जैसे ही फोन कटा। मदन राठौड़ ने अपने हजारों समर्थकों को ये बात बताई। समर्थक ज्यादातर लोग संघ और बीजेपी के ही थे। जो पार्टी की लगातार उपेक्षा से नाराज थे और पार्टी को सबक सिखाने के मूड में थे। लेकिन उनके लिए मोदी और शाह से बड़ा कोई हो नहीं सकता था। पीएम का फोन आना उन सबके लिए सम्मान की बात थी। कार्यकर्ताओं और खुद मदन राठौड़ के लिए पीएम मोदी से बड़ा कौन हो सकता था। उन्होंने कहा साहब का फोन है नाम वापस लेना पड़ेगा और सुमेरपुर सीट भी पार्टी को जीतानी पड़ेगी।

प्रदेशाध्यक्ष बने तो चमकी किस्मत

कुछ दिनों बाद जब सीपी जोशी को हटाकर नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की गई तो वो नाम मदन राठौड़ का था। जयपुर से लेकर पाली तक लोग फोन कर राठौड़ को बधाई देने लगे। इधर खुद मदन राठौड़ को ये भरोसा नहीं था कि पार्टी में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी। लोग उन्हें फोन कर रहे थे लेकिन वे कंफर्म नहीं थे। लेकिन जैसे ही दिल्ली से फोन आया बधाई आपको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। फिर राठौड़ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बस उसी दिन से मदन राठौड़ की जिंदगी अलग ही संवर गई।

अहम जिम्मेदारियों के बावजूद आए हाशिये पर-

अब आपको बताते हैं मदन राठौड़ की असल कहानी। मदन राठौड़ शुरू से ही आरएसएस के स्वंयसेवक रहे है। वर्ष 2003 और 2013 में सुमेरपुर से भाजपा के विधायक रहे। वसुंधरा राजे सरकार में सरकारी उप मुख्य सचेतक भी रहे। फिर उनका राजनीतिक साजिश के चलते सिटिंग एमएलए होते हुए भी अचानक टिकट काट दिया गया। उसके बाद वे लगातार पार्टी का काम देख रहे थे लेकिन पार्टी वहां नया नेतृत्व खड़ा कर चुकी थी। इसलिए उन्हें टिकट नहीं दिया गया। राजनीति में वे हासिये पर चले गए। वे हर बार टिकट की दावेदारी करते थे, लेकिन पार्टी ने जातिगत संतुलन का बहाना बनाकर उन्हें घर बैठा दिया गया।

जनगणना कार्य में लापरवाही पर जिला कलक्टर ने की सख्त कार्रवाई

जनगणना कार्मिक अंजू वर्मा निलंबित, कार्य में शिथिलता बरतने वालों को चेतावनी

जयपुर

जनगणना 2027 कार्य को गंभीरता एवं प्राथमिकता के साथ संपादित करने के निर्देशों की अवहेलना करने पर जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। जनगणना कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के मामले में मंगलवार को एक जनगणना कार्मिक को निलंबित किया गया है। प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं जिला कलक्टर संदेश नायक के आदेशानुसार जनगणना कार्य हेतु नियुक्त प्रगणक अंजू वर्मा, अध्यापिका लेवल-2 अंग्रेजी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डेहरा, जोबनेर को प्रधानाचार्य द्वारा कार्यमुक्त किए जाने के उपरांत भी चार्ज जनगणना अधिकारी एवं तहसीलदार जोबनेर द्वारा आवंटित एचएलबी संख्या 0152 का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। जनगणना जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के प्रति अकर्मण्यता, लापरवाही तथा संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना किए जाने को गंभीरता से लेते हुए प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं जिला कलक्टर द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान संबंधित कार्मिक का मुख्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जोबनेर निर्धारित किया गया है। जिला कलक्टर ने सभी जनगणना कार्मिकों को निर्देशित किया है कि वे सौंपे गए दायित्वों का समयबद्ध एवं गंभीरता के साथ निर्वहन सुनिश्चित करें, ताकि जनगणना जैसे देशहित के कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके।

जल जीवन मिशन कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित

जयपुर

जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले में संचालित कार्यों की समीक्षा बैठक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् प्रतिभा वर्मा की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित जल सेवा आकलन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए, ताकि जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों में आवश्यक सुधार हेतु कार्ययोजना तैयार कर अनुमोदन के लिए समय पर प्रेषित की जा सके। बैठक में जलापूर्ति व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी एवं सुचारू बनाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए गए। बैठक में जिले में संचालित जल सेवा आकलन कार्यक्रम एवं लंबित हर घर जल प्रमाणीकरण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान सरपंच संघ के अध्यक्ष एवं ग्राम विकास अधिकारी संघ के पदाधिकारियों के साथ ग्राम पंचायतों से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की गई। बैठक में हर घर जल प्रमाणीकरण से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करते हुए सरपंच संघ द्वारा विद्युत बिलों के भुगतान एवं योजनाओं के संचालन एवं संधारण से संबंधित विषय उठाए गए। बैठक में बताया गया कि जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य, जल जीवन मिशन 1.0 के शेष कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात ही प्रारंभ किए जा सकेंगे। अधिकारियों ने सरपंच संघ से हर घर जल प्रमाणीकरण कार्य में सक्रिय सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया, जिस पर सरपंच संघ द्वारा सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया गया। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों, विकास अधिकारियों एवं संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत शील की डूंगरी बांध पर आयोजित हुआ जन-जागरूकता कार्यक्रम

जल संरक्षण एवं पर्यावरण संवर्धन को जन आंदोलन बनाने का किया गया आह्वान

जयपुर

राजस्थान सरकार के महत्वाकांक्षी 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2026' के अंतर्गत सोमवार को शील की डूंगरी बांध पर जल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन एवं जन-जागरूकता को समर्पित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के लगभग 100 ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता भुवन भास्कर रहे। उनके नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ जल पूजन के साथ किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य जल अर्घ्य, कैलाश यात्रा, जल पर चुनरी अर्पण एवं सामूहिक जल शपथ जैसे आयोजनों के माध्यम से जल संरक्षण के प्रति जन-जागरण का संदेश दिया गया।

इस अवसर पर मुख्य अभियंता भुवन भास्कर ने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकारी दायित्व नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं जनभागीदारी आधारित जल प्रबंधन को समय की आवश्यकता बताते हुए सभी से जल संरक्षण के प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान बांध परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। उपस्थित ग्रामीणों एवं अधिकारियों ने पौधों के संरक्षण तथा जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लिया। साथ ही जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु सामूहिक प्रयास करने का संदेश दिया गया।

उल्लेखनीय है कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2026 के तहत राज्यभर में जल संरक्षण, पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से विविध गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। शील की डूंगरी बांध पर आयोजित यह कार्यक्रम जनभागीदारी आधारित जल संरक्षण प्रयासों का प्रेरणादायी उदाहरण है।

कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि गोपाल शर्मा, अधिशासी अभियंता अनिल थालोर, सहायक अभियंता अनुराधा चौधरी, चाकसू नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

वंदे-गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संरक्षण एवं जनजागरूकता गतिविधियों का व्यापक आयोजन

जल संसाधन, पीएचईडी एवं भूजल विभाग ने जनभागीदारी से चलाया अभियान

जयपुर

'वंदे-गंगा' जल संरक्षण जन अभियान-2026 के अंतर्गत मंगलवार को जयपुर जिले में जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) एवं भूजल विभाग द्वारा जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, भूजल संवर्धन एवं जनजागरूकता से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अभियान के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आमजन की सक्रिय सहभागिता के साथ जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने हेतु अनेक गतिविधियां आयोजित की गईं।

जिला कलक्टर संदेश नायक ने बताया कि जल संसाधन विभाग द्वारा जिले की विभिन्न नदियों, झीलों, सरोवरों, मध्यम बांधों एवं नहर स्थलों पर जल पूजन कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभाग द्वारा जल उपयोगिता संगमों एवं कृषकों के सहयोग से नहरों एवं खालों की साफ-सफाई तथा गाद निकालने (डी-सिल्टिंग) के कार्य कराए गए। साथ ही जल शक्ति अभियान कैच द रेन एवं जल संचय जनभागीदारी कार्यक्रमों के माध्यम से जल संरक्षण के प्रति जनजागरूकता

बढ़ाई गई। विभिन्न स्थलों पर नवीन कार्यों का भूमिपूजन एवं पूर्ण कार्यों का लोकार्पण एवं अवलोकन भी किया गया।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरटीडब्ल्यूएचएस) के निर्माण हेतु तकनीकी जानकारी प्रदान की गई। विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। जल बचत एवं जल संरक्षण संबंधी जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन को जल संरक्षण के महत्व से अवगत कराया गया। साथ ही जल परीक्षण अभियानों के माध्यम से नागरिकों को जल गुणवत्ता एवं सुरक्षित पेयजल के महत्व की जानकारी दी गई। भूजल विभाग द्वारा 'कर्मभूमि से मातृभूमि' अभियान के अंतर्गत विभिन्न सरकारी एवं सार्वजनिक परिसरों में वर्षा जल संचयन एवं भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का अवलोकन किया गया। इस दौरान रिचार्ज संरचनाओं के आस-पास स्वच्छता अभियान चलाकर वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई गई। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया।

इसके अतिरिक्त चित्रकूट एवं जगतपुरा क्षेत्र में नवीन वर्षा जल संचयन एवं भूजल पुनर्भरण संरचनाओं को अभियान में शामिल करते हुए उनकी स्वीकृति एवं पोर्टल पर अद्यतन करने की कार्यवाही की गई। अभियान के दौरान विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों एवं आमजन ने सक्रिय भागीदारी निभाते हुए जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

जिला प्रशासन द्वारा सभी विभागों को अधिकाधिक जनभागीदारी के साथ जल संरक्षण गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के अंतर्गत आयोजित विभिन्न गतिविधियों में बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता कर जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

नागरिक सेवाओं में सुगमता, पारदर्शिता और त्वरित समाधान की दिशा में जेडीए का सशक्त प्रयास

जयपुर

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के सुशासन के संकल्प तथा नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देशन में जयपुर विकास प्राधिकरण आमजन को सरल, सुलभ, पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण, डिजिटल माध्यमों के व्यापक उपयोग तथा नागरिक हितों को केंद्र में रखकर किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम यह है कि बड़ी संख्या में नागरिक विभिन्न सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तथा उनके प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है।

जेडीए द्वारा नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी एवं जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से विभिन्न ऑनलाइन एवं कार्यालयीय सेवाओं के माध्यम से मई माह में हजारों आवेदनों का समाधान सहित निस्तारण किया गया। इससे आमजन को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से राहत मिली है तथा सेवाओं की उपलब्धता अधिक सुगम हुई है।

जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि जेडीए द्वारा नागरिक सुविधाओं के विस्तार और सेवा वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में मई माह के दौरान कुल 3 हजार 119 आवेदनों पर कार्यवाही की गई, जिनमें से 2 हजार 845 प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण कर नागरिकों को सेवाओं का लाभ प्रदान किया गया।

उल्लेखनीय है की मई माह में सर्वाधिक नागरिकों ने ई-पट्टा (लीज/फ्रीहोल्ड डीड) जारी करने की सेवा का लाभ उठाया, जिसमें 1976 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके अतिरिक्त नाम हस्तांतरण के 429 प्रकरणों का समाधान किया गया। इसी के साथ ही पूर्व में जारी पट्टों के स्थान पर फ्रीहोल्ड ई-पट्टा जारी करने के 279 मामलों का निस्तारण किया गया। वहीं सब-डिवीजन एवं पुनर्गठन से संबंधित 148 प्रकरणों का समाधान किया गया तथा वन टाइम लीज सर्टिफिकेट (ओटीएलसी) के 13 प्रकरणों में सेवाएं प्रदान की गईं।

जेडीसी महाजन ने कहा कि जेडीए का उद्देश्य केवल सेवाएं प्रदान करना ही नहीं, बल्कि नागरिकों को पारदर्शी, त्वरित एवं भरोसेमंद प्रशासन उपलब्ध कराना है। इसी सोच के अनुरूप डिजिटल प्रक्रियाओं को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि प्रत्येक नागरिक को निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्राप्त हो सकें।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक संपादक: नीरज मेहरा द्वारा बोनस ग्राफिक्स, लक्ष्मी नगर, झोटवाड़ा मार्ग, अजमेर रोड़, जयपुर-302006 से मुद्रित एवं 141, दयानन्द नगर, फेज प्रथम झालना डूंगरी गली नंबर 19, थाना गांधी नगर, जयपुर (राज.) से प्रकाशित। प्रबंध संपादक- पी.के.बृजवाल, 9950325930, 9571635930 (कानूनी सलाहकार एडवोकेट कैलाशनाथ भट्ट)